कामये दुःखतप्तानाम्।
प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्॥

जागृति

वर्ष:64 अंक:10 मुम्बई सितम्बर 2020

एमएसएमई मंत्री द्वारा विक्रय हेतु रेशम खादी मास्क-उपहार बॉक्स की शुरुआत

आयोग ने 74वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

जागृति

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की औद्योगिकीकरण विषयक मासिक पत्रिका

वर्ष:64 अंक:10 मुम्बई सितम्बर 2020

सम्पादकीय मण्डल

अध्यक्ष
श्रीमती प्रीता वर्मा

संपादक
एम. राजन बाबू

सह संपादक
स्मिता जी. नायर

उप संपादक
सुबोध कुमार

वरिष्ठ हिंदी अनुवाद अधिकारी
सरस्वती खनका

डिजाईन व पृष्ठसज्जा
सुबोध कुमार

प्रचार, फ़िल्म एवं लोक शिक्षण
कार्यक्रम निदेशालय द्वारा
खादी और ग्रामोद्योग आयोग,
ग्रामोदय, 3 इर्ला रोड,
विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -400056
के लिए ई-प्रकाशित
ईमेल: kvicpub@gmail.com
वेबसाइट: www.kvic.org.in

आवश्यक नहीं कि पत्रिका में प्रकाशित लेखों तथा विचारों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग अथवा संपादक सहमत हों

इस अंक में

समाचार सार ..... 3 से 26

आयोग के अध्यक्ष का खादी प्रेमियों को एक पत्र.....

अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई मंत्री द्वारा एक नई योजना को मंजूरी .....

अड़चनों को दूर कर 2020 में पीएमईजीपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 44% की छलांग.....

एमएसएमई मंत्री द्वारा विक्रय हेतु रेशम खादी मास्क-उपहार बॉक्स की शुरुआत.....

प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करता हनी मिशन .....

अगरतला में खादी और ग्रामोद्योग आयोग और त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के संयुक्त कार्यालय भवन की आधारशिला रखी गयी.....

अरुणाचल प्रदेश में पहले सिल्क प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र के साथ खादी और पर्यटन को आयोग द्वारा प्रोत्साहन.....

खादी मास्क की लोकप्रियता बढ़ी; आयोग ने रेड क्रॉस सोसाइटी से 10.5 लाख फेस मास्क के लिए पुनः ऑर्डर प्राप्त किया.....

केवीआईसी द्वारा 'खादी एसेंशियल' और 'खादी ग्लोबल' को अवैधानिक रूप से खादी ब्रांड नाम के उपयोग के खिलाफ कानूनी नोटिस .....

फिक्की और केवीआईसी ने उत्तर-पूर्व में शहद उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया.....

एमएसएमई मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत गीत का शुभारंभ.....

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देशभक्ति के उत्साह के साथ 74वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया.....

आयोग के राज्य / मंडलीय कार्यालयों में 74 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया.....

आयोग के अध्यक्ष द्वारा सोनभद्र में खादी भंडार का उद्घाटन.....

आयोग द्वारा जल संरक्षण की एक पहल.....

हाथकागज और हाथकागज उत्पाद बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह..

आयोग के अध्यक्ष द्वारा खादी भंडार और सामान्य सुविधा केन्द्र इकाई का उद्घाटन.....

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विभागीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा 5 दिवसीय मधुमक्खीपालन प्रशिक्षण.....

आयोग के अध्यक्ष द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण में 50 प्रवासी श्रमिकों को 500 मधुमक्खी के बक्से वितरित.....

केरल में नवीनीकृत खादी भवन का उद्घाटन.....

पयन्नूर फ़िरखा खादी ग्रामोद्योग संघ, केरल ने पारंपरिक परिधानों की श्रृंखला के तहत अपने एक नए उत्पाद "सेट मुंडू" को विक्रय हेतु बाजार में उतारा.....

जगदलपुर में आयोग के कुम्हारों द्वारा एक छोटी लेकिन आदर्श पहल.....

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर .....27 से 31

आयोग के अध्यक्ष का खादी प्रेमियों को एक पत्र

प्रिय खादी प्रेमी,

खादी मास्क के लिए भारी प्रतिक्रिया उत्साहजनक है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग का प्रयास हमेशा समय पर उत्पादों को उपलब्ध करना है, लेकिन कुछ बाधाएं जो हमारे नियंत्रण से परे हैं, जिससे कारण कुछ विलम्ब हो सकता है, किन्तु हम आपकी हर समय सर्वश्रेष्ठ सेवा का आश्वासन देते हैं।

विनय कुमार सक्सेना
VINAI KUMAR SAXENA

अध्यक्ष
CHAIRMAN
खादी और ग्रामोद्योग आयोग
KHADI & VILLAGE INDUSTRIES COMMISSION
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises
भारत सरकार
Government of India

No: CS/Covid-19/2020-21
Date: 30/07/2020

Dear Khadi Lovers

I thank each one of you for the overwhelming response to Khadi Face Masks, the most eco-friendly and affordable product to fight Corona pandemic. We regret the delay in delivery of face masks owing to various factors that were totally beyond our control. However, I am sure you must have received your face masks by now or you will be receiving them soon as we have dispatched all orders till today.

We are working in the extraordinary situation of Covid-19 pandemic with limited workforce. We had maintained a stock of 50,000 face masks at the time of beginning the online sale on July 7. The buyers' response was, however, more than we expected. I would like to mention that like all other Khadi products, the Khadi face mask fabric is handcrafted which requires extra time and labor for our artisans to produce.

I would also mention that the Indian Postal Department is also working against odds to deliver the consignments at your doorsteps. Owing to shortage of manpower and transportation constraints, the department accepts consignments every alternate day, which adds to the delay. But I am pleased to inform you that our team worked overtime to make up for the delay.

While, we sincerely regret the delay, I would like to assure you that the KVIC would never compromise on the quality, which is the true essence of Khadi and the Gandhian principles. I would appreciate your feedback on Masks. Once again, thank you all for buying Khadi products. This is small but meaningful contribution towards empowering our artisans and realizing the Hon'ble Prime Minister's dream of "Aatmanirbhar Bharat".

Stay safe and healthy.

Yours truly
(Vinai Kumar Saxena)

गांधी दर्शन पवेलियन (गेट नं. 4), राजघाट, नई दिल्ली–110002 / Gandhi Darshan Pavilion (Gate No. 4), Rajghat, New Delhi-110002
Tel.: 011-23724690, 23724693, Fax: 011-23724693
'ग्रामोदय' 3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई–400056 / 'Gramodaya' 3, Irla Road, Vile Parle (West), Mumbai-400056
Tel.: 022-26202717 Fax: 022-26714109
Email : chairmankvic2015@gmail.com Website : kvic.org.in

अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एमएसएमई मंत्री द्वारा एक नई योजना को मंजूरी

केवीआईसी जल्द ही हजारों की संख्या में रोजगार सृजन और आयात निर्भरता को कम करने वाली प्रायोगिक परियोजना शुरु करेगा।

केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने अगरबत्ती उत्पादन में भारत को आत्म-निर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है।

'खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन' नाम के इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार पैदा करना और घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में पर्याप्त तेजी लाना है। इस प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी के लिए एमएसएमई मंत्रालय के समक्ष रखा गया था। प्रायोगिक परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी। इस परियोजना के पूर्ण कार्यान्वयन होने पर अगरबत्ती उद्योग में हजारों की संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन होगा।

निजी-सार्वजनिक मोड पर केवीआईसी द्वारा बनाई गई यह योजना इस मायने में अद्वितीय है कि बहुत कम निवेश में ही यह स्थायी रोजगार का सृजन करेगी और निजी अगरबत्ती निर्माताओं को उनके बिना किसी पूंजी निवेश के अगरबत्ती का उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगी। इस योजना के तहत, केवीआईसी सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन उपलब्ध कराएगा जो व्यापार भागीदारों के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। केवीआईसी ने केवल स्थानीय रूप से भारतीय निर्माताओं द्वारा निर्मित मशीनों की खरीद का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित करना भी है।

केवीआईसी मशीनों की लागत पर 25% सब्सिडी प्रदान करेगा और कारीगरों से हर महीने आसान किस्तों में शेष 75% की वसूली करेगा। व्यापार भागीदार कारीगरों को अगरबत्ती

बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराएगा और उन्हें काम के आधार पर मजदूरी का भुगतान करेगा। कारीगरों के प्रशिक्षण की लागत केवीआईसी और निजी व्यापार भागीदार के बीच साझा की जाएगी, जिसमें केवीआईसी लागत का 75% वहन करेगा, जबकि 25% व्यापार भागीदार द्वारा भुगतान किया जाएगा।

अगरबत्ती बनाने की प्रत्येक स्वचालित मशीन प्रति दिन लगभग 80 किलोग्राम अगरबत्ती बनाती है जिससे 4 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। अगरबत्ती बनाने की पांच मशीनों के सेट पर एक पाउडर मिक्सिंग मशीन दी जाएगी, जिससे 2 लोगों को रोजगार मिलेगा।

अभी अगरबत्ती बनाने की मजदूरी 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। इस दर से एक स्वचालित अगरबत्ती मशीन पर काम करने वाले 4 कारीगर 80 किलोग्राम अगरबत्ती बनाकर प्रतिदिन न्यूनतम 1200 रुपये कमाएंगे। इसलिए प्रत्येक कारीगर प्रति दिन कम से कम 300 रुपये कमाएगा। इसी तरह पाउडर मिक्सिंग मशीन पर प्रत्येक कारीगर को प्रति दिन 250 रुपये की निश्चित राशि मिलेगी।

योजना के अनुसार, व्यापार भागीदारों द्वारा साप्ताहिक आधार पर कारीगरों को मजदूरी सीधे उनके खातों में केवल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रदान की जाएगी। कारीगरों को कच्चे माल की आपूर्ति, लॉजिस्टिक्स, गुणवत्ता नियंत्रण और अंतिम उत्पाद का विपणन करना केवल व्यापार भागीदार की जिम्मेदारी होगी। मशीन की शेष 75% लागत की वसूली के बाद इसका मालिकाना हक स्वत: कारीगरों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

इस संबंध में पीपीपी मोड पर परियोजना के सफल संचालन के लिए केवीआईसी और निजी अगरबत्ती निर्माता के बीच दो-पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

इस योजना को दो प्रमुख फैसलों – अगरबत्ती के कच्चे माल पर आयात प्रतिबंध और बांस के डंडों पर आयात शुल्क में बढ़ोत्तरी, को देखते हुए बनाया गया। ये फैसले श्री नितिन गडकरी की पहल पर क्रमश: वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा लिए गए।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि केंद्र सरकार के दो फैसलों ने अगरबत्ती उद्योग में रोजगार के बड़े अवसर पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन के बड़े अवसर को भुनाने के लिए केवीआईसी ने 'खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन' नामक एक कार्यक्रम तैयार किया और मंजूरी के लिए एमएसएमई मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारीगरों का साथ देना और स्थानीय अगरबत्ती उद्योग की मदद करना है। देश में अगरबत्ती की वर्तमान खपत लगभग 1490 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। हालांकि, भारत में अगरबत्ती का उत्पादन प्रतिदिन केवल 760 मीट्रिक टन ही है। मांग और आपूर्ति के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए, इसमें रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं।

❑❑

अड़चनों को दूर कर 2020 में पीएमईजीपी परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 44% की छलांग

पीएमईजीपी परियोजनाओं को मंजूरी देने में जिला कलेक्टरों की भूमिका को समाप्त करने के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के निर्णय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, मौज़ूदा वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों अर्थात 1 अप्रैल, 2020 से 18 अगस्त, 2020 के दौरान परियोजनाओं की स्वीकृति में 44 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।

ऐसे समय में जब कोविड -19 लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भारी झटका लगा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित एक प्रमुख कार्यक्रम "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" काफी तेज़ी से आगे बढ़ा है । पीएमईजीपी परियोजनाओं को मंजूरी देने में जिला कलेक्टरों की भूमिका को समाप्त करने के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के निर्णय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, मौज़ूदा वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों अर्थात 1 अप्रैल, 2020 से 18 अगस्त, 2020 के दौरान परियोजनाओं की स्वीकृति में 44 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 71,556 परियोजनाओं की तुलना में 1.03 लाख परियोजना को मंजूरी दी और वित्त पोषण बैंक को अग्रेषित किया है, इस प्रकार तुलनात्मक रूप से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 44% की छलांग दर्ज हुई है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम केंद्र सरकार का प्रमुख रोजगार सृजन कार्यक्रम है और योजना को लागू करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग एक स्वतंत्र अभिकरण है। मंत्रालय ने इस वर्ष 28 अप्रैल को, पीएमईजीपी परियोजनाओं को मंजूरी देने में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की भूमिका से अलग करने के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी (डीएलटीएफसी) की भूमिका को पीएमईजीपी के तहत परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के समय अड़चन के रूप में देखा गया था और खादी और ग्रामोद्योग आयोग इस संदर्भ में जिला कलेक्टरों की भूमिका को समाप्त करने की मांग कर रहा था क्योंकि अक्सर यह देखा गया था कि इस महत्वपूर्ण योजना को न्यूनतम प्राथमिकता में रखा गया।

संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, जोकि पीएमईजीपी योजना को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है, को भावी उद्यमियों से आवेदन को स्वीकृति प्रदान करने और इसे क्रेडिट निर्णय लेने के लिए बैंकों को अग्रेषित करने का काम सौंपा गया था। अब तक, डीएलटीएफसी द्वारा प्रस्तावों की जांच की गई थी जो परियोजनाओं को मंजूरी देने में अक्सर देरी का कारण बनती थीं।

2020 में अप्रैल से अगस्त की अवधि के दौरान, वित्तपोषित बैंकों ने 11,191 परियोजनाओं को मंजूरी दी और 345.43 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी का वितरण आवेदकों को किया गया, जबकि गत वर्ष अर्थात वर्ष 2019 के प्रथम पांच महीनों में 9161 परियोजनाओं के लिए 276.09 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी का वितरण किया गया। इस प्रकार बैंकों

द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या में 22% की वृद्धि हुई जबकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मार्जिन मनी के संवितरण में गत वर्ष की तुलना में 24% ज़्यादा वृद्धि हुई।

यह वर्ष पीएमईजीपी परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन में अत्याधिक महत्व रखता है वह भी तब जब कि पूरे देश में इन पांच महीनों के अधिकांश समय लॉकडाऊन लागू रहा। परियोजनाओं की संख्या अधिक होना, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देकर लोगों के लिए स्वरोजगार और स्थायी आजीविका बनाने के सरकार के संकल्प का प्रतीक हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि पीएमईजीपी परियोजनाओं के अनुमोदन में भारी वृद्धि माननीय प्रधानमंत्री के "मिनिमम गवर्मेन्ट मैग्ज़िमम गवर्नेन्स' के आह्वान का परिणाम है। "जिला कलेक्टरों की भूमिका को बंद करने से परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन सुनिश्चित हुआ है। हालाँकि, बैंकों को भी धनराशि स्वीकृत करने की प्रक्रिया में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक संख्या में आवेदकों को लाभ मिल सके। श्री सक्सेना ने कहा कि परियोजनाओं के निष्पादन और देश में रोजगार सृजन के लिए धन का वितरण समय पर किया जाना अति महत्वपूर्ण है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

वर्ष 2019 और 2020 में 1 अप्रैल से 18 अगस्त तक प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के प्रदर्शन की तुलना

विवरण	1 अप्रैल से 18 अगस्त 2019 तक		1 अप्रैल से 18 अगस्त 2020 तक		विकास % में	
प्राप्त आवेदनों की संख्या	168848		178003		5%	
बैंकों को वित्तपोषण के लिए आयोग द्वारा अग्रेषित आवेदनों की संख्या	71556		103003		44%	
	बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	आयोग द्वारा वितरित मार्जिन मनी	बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	आयोग द्वारा वितरित मार्जिन मनी	बैंकों द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	आयोग द्वारा वितरित मार्जिन मनी
	9161	रु 276.09 करोड़	11,191	रु 345.43 करोड़	22%	24%

एमएसएमई मंत्री द्वारा विक्रय हेतु रेशम खादी मास्क -उपहार बॉक्स की शुरुआत

अब आप अपने परिवार और दोस्तों को उपहार में खास तौर पर तैयार किए गए खादी रेशम फेस मास्क का एक आकर्षक उपहार बॉक्स दे सकते हैं । केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 01 अगस्त, 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) द्वारा विकसित उपहार बॉक्स का शुभारंभ किया । उपहार बॉक्स में विभिन्न रंगों और प्रिंटों में चार दस्तकारी रेशम के मास्क होते हैं। मास्क को सुनहरा उभरे हुए मुद्रण के साथ एक सुंदर रूप से तैयार किए गए हस्तनिर्मित काले रंग के पेपर बॉक्स में पैक किया गया है।

श्री गडकरी ने उपहार बॉक्स की सराहना करते हुए कहा कि यह सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ त्योहारों का जश्न मनाने का एक उपयुक्त उत्पाद है। उन्होंने केवीआईसी की मास्क बनाने की पहल की सराहना करते हुए कहा कि इससे कारीगरों को कोरोना महामारी के सबसे कठिन समय के दौरान स्थायी आजीविका मिलती है।

रेशम मास्क उपहार बॉक्स की कीमत सिर्फ 500 रुपये प्रति बॉक्स है और अब दिल्ली एनसीआर में केवीआईसी के सभी आउटलेट्स पर उपलब्ध है।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि उपहार बॉक्स लॉन्च करने के पीछे का विचार विदेशी बाजार और त्योहारों के मौसम के दौरान अपने प्रियजनों के लिए उचित मूल्य के उपहारों की तलाश कर रहे एक बड़ी भारतीय आबादी की मांग को पूरा करना है।

उपहार बक्से में एक मुद्रित रेशम मास्क और तीन अन्य मास्क आकर्षक रंगों में होंगे। ये तीन स्तरीय रेशम मास्क त्वचा के अनुकूल, धोने योग्य, पुन: उपयोग योग्य, और स्वाभिवक रूप से जैव विघटन योग्य हैं।

सिल्क मास्क में तीन परतें होती हैं और कान में लगाने वाले लूप को आसानी से समायोजित किया जा सकता है। इसमें 100% खादी सूती कपड़े की दो आंतरिक परतें और रेशम कपड़े की एक शीर्ष परत है।

❖❖

प्रवासी कामगारों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करता हनी मिशन;

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 700 मधुमक्खी बक्सों का वितरण

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने प्रमुख "हनी मिशन" कार्यक्रम के माध्यम से प्रवासी कामगारों को स्थानीय रोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर "आत्मनिर्भर भारत" की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है।

केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री प्रताप चंद्र सारंगी ने 25 अगस्त, 2020 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और बुलंदशहर जिलों के 70 प्रवासी कामगारों के बीच 700 मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया और इस प्रकार से उन्हें हनी मिशन के अंतर्गत आजीविका का अवसर प्रदान किया।

ये प्रवासी कामगार- सहारनपुर के 40 और बुलंदशहर के 30 - कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों से अपने गृहनगर लौट आए थे, और कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे। प्रधानमंत्री द्वारा "आत्मनिर्भर भारत" के लिए किए गए आह्वान के बाद, केवीआईसी ने इन कामगारों की पहचान की, उन्हें मधुमक्खी पालन के लिए 5 दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया और मधुमक्खी पालन गतिविधियों को शुरू करने के लिए उन्हें आवश्यक टूल किट और मधुमक्खी बक्से प्रदान किए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का समस्त क्षेत्र, वनस्पतियों की

बहुतायत के साथ, जिसमें विभिन्न प्रकार की फसलें शामिल हैं, शहद उत्पादन के लिए आदर्श क्षेत्र है। केवीआईसी प्रशिक्षण केंद्र, पंजोखेरा में मधुमक्खी के बक्सों का वितरण किया गया।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री सारंगी ने इस पहल की सराहना की और कहा कि मधुमक्खी पालन में इन कामगारों को शामिल करने से स्थानीय रोजगार का सृजन होगा; यह भारत के शहद उत्पादन को बढ़ावा देने में भी योगदान करेगा जो कि हनी मिशन का मुख्य उद्देश्य है। मंत्री महोदय ने कहा, "यह एक बड़ी पहल है। प्रवासी कामगारों को उनके दरवाजे पर रोजगार का अवसर प्रदान करने से वे आत्मनिर्भर बनेंगे।"

इस अवसर पर उपस्थित, केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि मधुमक्खी पालन में प्रवासी कामगारों को शामिल करना, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर 'आत्मनिर्भरता' के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आह्वान के साथ एक प्रकार से समरुपण है। "मधुमक्खी पालन से न केवल भारत में शहद उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि इससे मधुमक्खी पालकों की आय में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा, मधुमक्खी मोम, पराग, गोंद, रॉयल जेली और मधुमक्खी का विष जैसे उत्पाद भी बाजार में उपलब्ध होंगे और इसलिए, स्थानीय लोगों के लिए यह एक लाभदायक प्रस्ताव है।"

प्रवासी कामगारों, जिन्हें मधुमक्खी के बक्से और टूल किट उपलब्ध कराए गए, ने सरकारी सहायता पर खुशी व्यक्त की और अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि उन्हें अब अन्य राज्यों में नौकरियों की तलाश करने के लिए अपना घर छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। कर्नाटक से अपने गृहनगर सहारनपुर लौटने वाले अंकित कुमार ने कहा कि वे लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए थे। हालांकि, केवीआईसी द्वारा समर्थन प्रदान किए जाने के साथ ही उन्हें अब स्वरोजगार फिर से प्राप्त हो गया है। महाराष्ट्र में काम करने वाले एक अन्य प्रवासी कामगार मोहित ने बताया कि अब उन्हें दूसरे शहरों में नौकरी की तलाश करने के कारण अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा और हनी मिशन से जुड़कर वे अपने लिए बेहतर आजीविका का निर्माण कर सकेंगे।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि, केवीआईसी द्वारा 3 वर्ष पहले शुरू किए गए हनी मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, आदिवासियों, महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को मधुमक्खी पालन में शामिल करके रोजगार के अवसर उत्पन्न करना और भारत में शहद उत्पादन को बढ़ावा देना है। अब तक केवीआईसी ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में 1.35 लाख से ज्यादा मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया है। इसके कारण देश भर में 13,500 लोगों को फायदा पहुंचा है जबकि लगभग 8,500 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन हुआ है।

अगरतला में खादी और ग्रामोद्योग आयोग और त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के संयुक्त कार्यालय भवन की आधारशिला रखी गयी

इससे बांस और शहद उद्योग को व्यापक लाभ मिलेगा

त्रिपुरा में खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (टीकेवीआईबी) के संयुक्त कार्यालय भवन के लिए 8 साल पुरानी परियोजना अब एक ठोस आकार ले रही है।

त्रिपुरा के माननीय मुख्यमंत्री श्री बिप्लब कुमार देब और केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने आज संयुक्त रूप से त्रिपुरा में कार्यालय भवन के लिए आधारशिला रखी, जबकि त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड ने भवन के लिए भूमि उपलब्ध करायी है, केवीआईसी ने भवन निर्माण के लिए 7.72 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसमें से केवीआईसी पहले ही 4 करोड़ रुपये जारी कर चुका है और यह निर्माण कार्य एक साल में पूरा हो जाएगा।

इस अवसर पर बोलते हुए, श्री बिप्लब कुमार देब ने

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की पहल की सराहना की और कहा कि संयुक्त कार्यालय भवन राज्य में विभिन्न परियोजनाओं के उचित समन्वय और त्वरित निष्पादन को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, "त्रिपुरा सरकार और केवीआईसी मिलकर राज्य में अगरबत्ती के लिए बांस की लकड़ियों का उत्पादन बढ़ाने पर काम करेंगे, जो 29,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष से घटकर महज 1400 मीट्रिक टन हो गई है। राज्य में बांस की प्रचुरता को देखते हुए बांस आधारित अन्य उद्योगों की भी बहुत बड़ी संभावना है। हमने बांस की बोतलों का उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है और यहां तक कि बांस की बोतलों में स्थानीय रूप से उत्पादित शहद की पैकेजिंग शुरू की है, जो एक अनूठा कदम है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने राज्य में बांस की विशाल क्षमता पर भी जोर देते हुए कहा कि त्रिपुरा देश को बांस की छड़ियों (स्टिक्स) के निर्माण में नेतृत्व कर सकता है और अगरबत्ती उत्पादन में भारत

को आत्मानिर्भर बनाने में योगदान दे सकता है। "कच्चे माल की प्रचुरता, यानी राज्य में उपलब्ध बांस के साथ, त्रिपुरा बांस की छड़ें (स्टिक्स) बनाने में अग्रणी हो सकता है। सक्सेना ने कहा कि खासतौर पर बांस की लकड़ियों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी के बाद स्थानीय विनिर्माण के लिए बहुत बड़ा अवसर है।

उन्होंने यह भी कहा कि त्रिपुरा देश में उच्च गुणवत्ता वाले रबड़ शहद का प्रमुख उत्पादक बन सकता है जो राज्य में अच्छी मात्रा में उत्पादित होता है। त्रिपुरा में मधुमक्खी पालन अब तक एक अप्रयुक्त स्रोत था और राज्य में केवीआईसी द्वारा 3000 मधुमक्खी बक्से वितरित करने के बाद ही गतिविधियों में तेजी आई।

श्री सक्सेना ने ग्रामीण रोजगार सृजन के लिए विभिन्न परियोजनाओं को लागू करने में त्रिपुरा सरकार और त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के समर्थन का आश्वासन दिया।

विशेष रूप से, कार्यालय भवन के लिए प्रस्ताव 2012 में शुरू किया गया था; हालांकि, दिसंबर 2019 में केवीआईसी के अध्यक्ष की त्रिपुरा की यात्रा के दौरान ही इसके काम को गति प्रदान की गयी और केवल 2 महीने में, यानी जनवरी 2020 में, आयोग ने 1650 वर्ग फुट से अधिक की 3 मंजिला इमारत के निर्माण के लिए 4 करोड़ रुपये मंजूरी दे दी थी।

इस इमारत में बिक्री आउटलेट, प्रदर्शन केंद्र और खादी संस्थाओं, पीएमईजीपी, एसएफयूआरटीआई और केआरडीपी के उत्पादों के लिए प्रावधान होगा। हालांकि, कोविड -19 लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य बंद हो गया था।

❑❑

अरुणाचल प्रदेश में पहले सिल्क प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र के साथ खादी और पर्यटन को आयोग द्वारा प्रोत्साहन

अरुणाचल प्रदेश के दूरदराज के आदिवासी गांव चुल्लियु में जल्द ही कताई और बुनाई की गतिविधियों की हलचल बढ़ेगी क्योंकि खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) जल्द ही वहां एक सिल्क प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलने जा रहा है जो राज्य में अपने प्रकार का पहला केंद्र होगा। इस केंद्र की परिकल्पना महज छह महीने पहले की गई थी और यह सितंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाएगा।

केवीआईसी ने एक जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत करवाकर उसे प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में बदल दिया है। केवीआईसी को यह स्कूल भवन अरुणाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया गया है।

इस केंद्र पर हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और रैपिंग ड्रम जैसी मशीनें पहले ही आ चुकी हैं और मशीनों को स्थापित करने का काम जोरों पर है। प्रशिक्षण शुरू करने के लिए चुल्लियु गांव के 25 स्थानीय कारीगरों को पहले बैच के लिए चुना गया है।

इस परियोजना की परिकल्पना इसी साल फरवरी में उस दौरान की गई थी जब केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने इस आदिवासी गांव चुल्लियु के दौरे पर गए थे। श्री सक्सेना ने उस गांव में रेशम उत्पादन एवं ग्रामोद्योग संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए जबरदस्त क्षमता की पहचान करते हुए एरी सिल्क के लिए प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी दी थी। एरी सिल्क को पारंपरिक रूप से स्थानीय आदिवासियों द्वारा पहना जाता है। हालांकि कोविड-19 संबंधी लॉकडाउन के कारण कार्यों की प्रगति की रफ्तार सुस्त पड़ गई थी।

हाल ही में केवीआईसी ने चुल्लियु गांव में 250 मधुमक्खी के बक्सों का वितरण किया था। वहां अधिक ऊंचाई

(शेष पृष्ठ 26 पर)

खादी मास्क की लोकप्रियता बढ़ी; आयोग ने रेड क्रॉस सोसाइटी से 10.5 लाख फेस मास्क के लिए पुनः ऑर्डर प्राप्त किया

खादी और ग्रामोद्योग आयोग को भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी (आईआरसीएस) से 10.5 लाख उच्च गुणवत्ता वाले फेस मास्क की आपूर्ति के लिए एक दोहरा आदेश और अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। यह नया खरीद आदेश अपने पिछले आदेश के 1.80 लाख फेस मास्क के एक महीने से भी कम समय में आया है, जिसमें से खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने सोसाइटी को 1.60 लाख फेस मास्क की आपूर्ति की है।

यह 3.30 करोड़ रुपये का नया खरीद आदेश हाल ही में प्राप्त हुआ है और इसकी आपूर्ति इस सप्ताह से शुरू होगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग पहले ऑर्डर की आपूर्ति एक दो दिनों में पूरी कर लेगा। फेस मास्क पहले आदेश के अनुसार दिये गये आपूर्ति के समान होंगे। आईआरसीएस का यह नया आदेश केवीआईसी द्वारा मास्क की उत्कृष्ट गुणवत्ता और समय पर आपूर्ति का ही परिणाम है।

माननीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मास्क बनाने की गतिविधियों के माध्यम से देश में स्थायी रोजगार पैदा करने में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि फेस मास्क कोरोना रोग के खिलाफ सबसे प्रभावी सुरक्षात्मक उपाय बन गया; इसके उत्पादन ने कारीगरों के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन किया है।

यह विस्तार स्थानीय उत्पादन के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है क्योंकि इससे खादी कारीगरों के लिए लगभग 50,000 अतिरिक्त मानव कार्य दिवस पैदा होंगे। इस आदेश के क्रियान्वयन के लिए 1 लाख मीटर से अधिक के हाथ कते सूती खादी कपड़े की आवश्यकता होगी जिसकी आपूर्ति विभिन्न राज्यों के खादी संस्थाओं द्वारा की जाएगी। यह कताई और बुनाई की गतिविधियों को एक प्रेरणा देगा और कारीगरों के लिए रोजगार पैदा करेगा।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने आईआरसीएस के नए खरीद आदेश का स्वागत करते हुए कहा, "चरखा आर्थिक स्वतंत्रता का उपकरण है। इस कठिन समय के दौरान इस तरह के बड़े आदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि कताई और बुनाई की गतिविधियाँ जारी रहें और हमारे खादी कारीगरों के लिए आर्थिक स्थिरता आए।

विशेष रूप से, केवीआईसी द्वारा प्राप्त खादी फेस मास्क की आपूर्ति के लिए यह सबसे बड़ा ऑर्डर है। इससे पहले, जम्मू और कश्मीर सरकार ने लॉकडाउन के दौरान 7 लाख मास्क खरीदे थे। केवीआईसी को राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और आम जनता से केवीआईसी के ई-पोर्टल के माध्यम से बार-बार आदेश प्राप्त हुए हैं।

आईआरसीएस मास्क लाल पाइपिंग के साथ भूरे रंग में 100% डबल-ट्विस्टेड हाथकते सूती कपड़े से बने हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने विशेष रूप से भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के लिए इन डबल-ट्विस्टेड कॉटन मास्क को उनके द्वारा प्रदान किए गए नमूनों के अनुसार डिज़ाइन किया है। मास्क में बाईं ओर एक आईआरसीटी लोगो और दाईं ओर खादी इंडिया टैग है। अन्य खादी फेस मास्क की तरह, आईआरसीएस के लिए बने मास्क भी धोने योग्य, पुन: प्रयोज्य, त्वचा के अनुकूल और जैव-विघटन योग्य हैं।

केवीआईसी द्वारा 'खादी एसेंशियल' और 'खादी ग्लोबल' को अवैधानिक रूप से खादी ब्रांड नाम के उपयोग के खिलाफ कानूनी नोटिस

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) ने दो कंपनियों - 'खादी एसेंशियल' और 'खादी ग्लोबल' को कानूनी नोटिस जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि वे 'खादी' ब्रांड नाम का 'अनधिकृत रूप से' और 'कपटपूर्वक' उपयोग कर रहे हैं। केवीआईसी ने 21 अगस्त, 2020 को एक बयान में कहा कि दोनों कंपनियां ब्रांड नाम "खादी" का उपयोग करके विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से कई तरह के कॉस्मेटिक और सौंदर्य उत्पादों को बेचने में लगी हुई हैं और इस तरह उपभोक्ताओं को गुमराह कर रही हैं।

अगस्त के पहले सप्ताह में 'खादी एसेंशियल' और 'खादी ग्लोबल' को दिए गए नोटिस में केवीआईसी ने दोनों कंपनियों को ब्रांड नाम "खादी" का उपयोग करके अपने उत्पादों की बिक्री या प्रचार को तुरंत बंद करने और डोमेन नाम www.khadiessentials.com और www.khadiglobalstore.com को रद्द करने को कहा है। दोनों कंपनियों को ट्विटर,फेसबुक,इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपने सोशल मीडिया हैंडल को भी बंद करने के लिए कहा गया है।

कानूनी नोटिस में दोनों कंपनियों को कहा गया है कि "मार्क को अपनाकर उसका उपयोग उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए किया जा रहा है स्पष्ट है कि आपके मार्क को लेकर बाजार में पूरा भरोसा है और इसका उद्देश्य खादी ट्रेडमार्क की सद्भावना और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करना है। कानूनी नोटिस में कहा गया है कि खादी इंडिया के अलावा, ट्रेडमार्क "खादी" का उपयोग केवल अधिकृत लाइसेंसधारी या फ्रेंचाइजी धारकों द्वारा ही किया जा सकता है।" "केवीआईसी के ट्रेडमार्क को पूरी तरह से निर्धारित करने वाले मार्क का उपयोग समान वस्तुओं के लिए करना निस्संदेह बाजार में भ्रम और धोखे का कारण बनेगा। नोटिस में आगे कहा गया है कि मार्क का इस्तेमाल करना "खादी" ट्रेडमार्क का दुरुपयोग और गलत प्रतिनिधित्व होगा।

दोनों कंपनियों को कड़े शब्दों में कहा गया कि वे "खादी" के ब्रांड नाम का उपयोग करके उत्पादों की बिक्री पर तुरंत रोक लगाएं और सभी उत्पाद पैकेजिंग, लेबल, प्रचार सामग्री, साइनबोर्ड और क्रमश: खादी असेन्शल तथा खादी ग्लोबल से जुड़े किसी भी अन्य व्यावसायिक स्टेशनरी को शीघ्र नष्ट कर दें। केवीआईसी ने कहा है कि सात दिनों में निर्देशों का पालन करने में विफल रहने पर दोनों कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

केवीआईसी के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा कि "खादी" ब्रांड नाम का कोई भी दुरुपयोग हमारे कारीगरों की आजीविका पर सीधा असर डालता है जो भारत के दूरदराज के इलाकों में वास्तविक दस्तकारी उत्पाद बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवीआईसी ब्रांड नाम "खादी" का दुरुपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। श्री सक्सेना ने कहा कि यह खादी कारीगरों के हितों की रक्षा करना और खादी के नाम पर किसी भी तरह के नकली उत्पाद की बिक्री

(शेष पृष्ठ 26 पर)

फिक्की और केवीआईसी ने उत्तर-पूर्व में शहद उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाया

अगरतला, 29 अगस्त, 2020: खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने फिक्की और केवीआईसी द्वारा बागवानी निदेशालय, असम सरकार के समर्थन से आयोजित "हनी सीजन 2020" पर पहले ऑनलाइन राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कहा, केवीआईसी शहद उद्योग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। उन्होंने मधुमक्खी पालन और शहद उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उद्योग निकाय द्वारा की गई अनूठी पहल पर फिक्की की सराहना की।

उन्होंने आगे कहा, त्रिपुरा में रबड़ के शहद की तरह, उत्तर-पूर्व में शहद के उत्पादन की विशेष संभावनाएं हैं, विशेष रूप से विशिष्ट गुणों वाले मोनो फ्लोरल शहद की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि केवीआईसी सुदूर क्षेत्रों में मधुमक्खी पालकों के लाभ के लिए मोबाइल हनी प्रोसेसिंग इकाई विकसित करने पर काम कर रहा है। उसने आगे बताया, "केवीआईसी ने एक ही दिन में मधुमक्खी के बक्से के वितरण में एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हनी मिशन के तहत काजीरंगा के आसपास के ग्रामीणों को 1000 मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए हैं।"

श्री रंजीत बारठाकुर, अध्यक्ष, फिक्की- पूर्वोत्तर सलाहकार परिषद, ने अपने स्वागत भाषण में, निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रकृति को एकीकृत करने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "सकारात्मक व्यापार संरचना एवं अवसरों और रोजगार से जुड़े अनुमानों से पता चलता है कि 2030 तक $ 20 बिलियन की वार्षिक बचत और राजस्व हो सकता है – (2030 को चिह्नित करना, जो दुनिया भर में गरीबी उन्मूलन और स्थायी विकास प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा निर्धारित बेंचमार्क है)। यह समय है कि उद्योगों और कंपनियों ने सामूहिक नेतृत्व की मदद से लचीलापन बनना शुरू किया है, और प्रेरक कंपनियां और सरकारें वर्तमान कोरोना वायरस महामारी से सीख सकती हैं और प्रकृति को अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में एकीकृत कर सकती हैं।"

डॉ. सुबोध जिंदल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन भी इस अवसर पर उपस्थित थे, जिन्होंने ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए भारत में मधुमक्खी पालन की रणनीति को बदलने के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में पूर्वोत्तर और भारत के अन्य राज्यों के 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान उपस्थित अन्य लोगों में शामिल बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के निदेशक अब्दुल जलील ने असम राज्य में शहद उद्योग को विकसित करने के लिए उनके विभाग द्वारा की गई पहल के बारे में सविस्तार से बताया।

आयोग के पूर्व उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जवाहर लाल चौधरी ने मधुमक्खी संबंधी बीमारियों और बीमारियों को कवर करने वाली बीमा पॉलिसियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया, डॉ. सुकमल देब, आयोग के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रभारी, पूर्वोत्तर क्षेत्र, श्री अनूप धानुका, एमडी, केजरीवाल हनी, श्री सागर कुरडे, एमडी, सुमन फूड सलाहकार, श्री एन.के. लोथा, टीम के सदस्य और नोडल, नागालैंड हनी मिशन, ने मधुमक्खीपालन और शहद उद्योग के विभिन्न पहलों पर बात की और शुरुआत से अब तक की सफलता की कहानी पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में श्री एल. अब्राहम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रिया फूड्स, श्री मनोज कुमार दास, एमडी, एनईआरएएमएसी, श्री एस. भट्टाचार्यजी, अध्यक्ष, एग्रो-फूड प्रोसेसिंग और नॉन-टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की उप-समिति, फिक्की-नॉर्थन एडवाइजरी काउंसिल भी उपस्थित थे।

एक वेबिनार "एंटरप्रिन्योर इंडिया टीवी " द्वारा आयोजित

"आत्मनिर्भर भारत होगा हमारा....."
एमएसएमई मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत गीत का शुभारंभ

केन्द्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नितिन गडकरी ने "मिशन आत्मनिर्भर भारत" के तहत 23 अगस्त, 2020 को आत्मनिर्भर भारत पर एक गीत और उद्यमियों के लिए एक दैनिक लाइव कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने लाइव शो "गाँव से ग्लोब तक" को संबोधित किया और शीर्ष वैज्ञानिक, एग्री टेक्नोक्रेट, आईआईएम प्रबंधन टीम, शीर्ष बैंकरों, ट्रेड एसोसिएशन प्रमुखों, विश्वविद्यालय के कुलपति, पेशेवर एसोसिएशन, सामाजिक उद्यमियों और आईआईडी टीम के प्रमुखों के साथ एक पैनल चर्चा की।

यह कार्यक्रम "एंटरप्रिन्योर इंडिया टीवी " यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया गया था।

अपने उद्घाटन संबोधन में माननीय मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए ज्ञान को धन में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। 'स्मार्ट विलेज' बनाने के लिए उद्यम को उद्यमिता में विकसित किया जाना चाहिए। नवोन्मेष और विज्ञान ने इस सफलता को आगे बढ़ाया है। आगे बोलते हुए उन्होंने यह भी बताया कि एमएसएमई का लक्ष्य आने वाले वर्षों में 11 करोड़ नौकरियां पैदा करना है, यह 5 करोड़ खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से होगी।

Virtual Inauguration of Atmanirbhar Bharat Programme & Song || Chief Guest Shri. Nitin Gadkari Ji

इस अवसर पर बोलते हुए खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने कहा, केवीआईसी गांवों को सशक्त बनाने के लिए काम करता है और केवीआईसी को गांवों में अधिक से अधिक रोजगार विकसित करना अनिवार्य है। " उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर का अर्थ अंदर की ओर देखना नहीं है, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि केवीआईसी ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने, मधुमक्खी पालन करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान करने, अपशिष्ट प्लास्टिक के माध्यम से हस्तनिर्मित कागज विकसित करने, चर्म कार्य और मोरिंगा वृक्षारोपण आदि के माध्यम से कई मजबूत कदम उठाए हैं।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देशभक्ति के उत्साह के साथ 74वाँ स्वतंत्रता दिवस मनाया

मुंबई, 15 अगस्त 2020: 15 अगस्त 2020 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 74 वां स्वतंत्रता दिवस देशभक्ति के जोश के साथ मनाया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सुश्री प्रीता वर्मा ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग के मुख्यालय मुंबई में आयोजित ध्वजारोहण समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया ।

74वाँ
स्वतंत्रता दिवस

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा कोविड-19 महामारी पर सुरक्षा के लिए जारी किए गए सभी आवश्यक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए ध्वजारोहण समारोह में भाग लिया।

सुश्री प्रीता वर्मा ने 74 वें स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कोविड -19 महामारी के दौरान अथक परिश्रम करने वाले प्रथम पंक्ति के सभी योद्धाओं को याद किया।

अपने संबोधन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की भूमिका हमेशा से ही प्रासंगिक रही है और खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने इस महामारी के दौरान अपनी प्रासंगिकता को साबित करते हुए प्रवासी मजदूरों को भोजन के पैकेट और मास्क वितरित कर मदद की।

उन्होंने कहा कि, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से

कोविड -19 महामारी के दौरान 9 लाख निःशुल्क मास्क वितरित करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

श्रेष्ठ प्रदर्शन वाले क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए स्वर्ण, रजत और कांस्य शील्ड से सम्मानित किया गया।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय उद्योगों को अधिक प्रोत्साहन देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आत्म निर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल जैसे कई और कार्यक्रमों की शुरुआत की है।

❖❖

आयोग के राज्य / मंडलीय कार्यालयों में 74 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया

राज्य कार्यालय, अहमदाबाद

एमडीटीसी, बोरीवली, मुंबई

राज्य कार्यालय, जयपुर

मण्डलीय कार्यालय, गोरखपुर

राज्य कार्यालय, त्रिपुरा

राज्य कार्यालय, भोपाल

राज्य कार्यालय, रायपुर

मण्डलीय कार्यालय, मदुरै

आयोग के राज्य / मंडलीय कार्यालयों में 74 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया

मण्डलीय कार्यालय, मेरठ

उप कार्यालय, त्रिचूर

केएनएचपीआई, जयपुर

एमडीटीसी, त्रिचूर

राज्य कार्यालय, लखनऊ

मण्डलीय कार्यालय,वाराणसी

राज्य कार्यालय, जम्मू कश्मीर

राज्य कार्यालय, देहरादून

आयोग के अध्यक्ष द्वारा सोनभद्र में खादी भंडार का उद्घाटन

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 22 अगस्त, 2020 को सोनभद्र जिले के बनवसी सेवा आश्रम में एक सामान्य सुविधा केंद्र और खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया।

आयोग के अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि 'केवीआईसी द्वारा किए गए इस अधोसंरचना के विकास से कारीगरों की उत्पादकता बढ़ेगी जिससे उच्च आय होगी।

उन्होंने आगे कहा कि खादी सतत ग्रामीण विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

❖❖

आयोग के बहुउद्देश्यीय प्रशिक्षण केन्द्र, बाड़मेर द्वारा चरखा अभियांत्रिकी पर एक महीने का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया ।

आयोग के अध्यक्ष द्वारा बिहार के पूर्वी चंपारण में 50 प्रवासी श्रमिकों को 500 मधुमक्खी के बक्से वितरित

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने 30 अगस्त, 2020 को बिहार के पूर्वी चंपारण में हनी मिशन के तहत 500 मधुमक्खी बक्सों का वितरण किया।

इस अवसर पर आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि यह वह भूमि है जहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह एक सदी पहले शुरु किया था। आज, फिर से यहां आत्म निर्भरता का अध्याय शुरु हुआ है।

हाथकागज और हाथकागज उत्पाद बनाने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन समारोह

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष ने कुमारप्पा नेशनल हैंडमेड पेपर इंस्टीट्यूट, जयपुर में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हाथकागज और हाथकागज उत्पाद बनाने पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के पहले बैच के समापन सत्र को संबोधित किया।

श्री बी.एल. मीणा, निदेशक, राज्य कार्यालय, जयपुर ने वहां प्रशिक्षण पूरा होने के बाद प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए।

आयोग के अध्यक्ष द्वारा खादी भंडार और सामान्य सुविधा केन्द्र इकाई का उद्घाटन

आयोग के अध्यक्ष श्री विनय कुमार सक्सेना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 29 अगस्त, 2020 को कादीपुर में खादी भंडार, सामान्य सुविधा केन्द्र व परिधान इकाई और गाजीपुर जिले के काशीमाबाद में एक खादी भंडार का उद्घाटन किया। ये खादी भंडार , ग्राम सेवा आश्रम द्वारा चलाए जाते हैं।

अपने संबोधन में, आयोग के अध्यक्ष ने कारीगरों की सराहना की और उन्हें अपनी सामाजिक स्थिति और दैनिक आय को उन्नत करने के लिए और अधिक सक्रिय होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने ग्राम सेवा आश्रम को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

आत्मनिर्भर भारत के तहत विभागीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा 5 दिवसीय मधुमक्खीपालन प्रशिक्षण

आयोग के विभागीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा प्रयागराज जिले के झूंसी में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 4 अगस्त 2020 से 5 दिवसीय मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण शुरू

किया गया। मधुमक्खी पालन पर प्रशिक्षण का यह दूसरा बैच है, इस प्रशिक्षण में 30 प्रवासी बेरोजगारों ने भाग लिया।

आयोग के विभागीय कार्यालय, वाराणसी के उप निदेशक प्रभारी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने, प्रतिभागियों को मधु क्रांति (हनी मिशन) के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा उन्हें मधुमक्खी पालन उद्योग को अपनाने और इस उद्योग के तहत अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया।

नवाचार और नई पहल

आयोग द्वारा जल संरक्षण की एक पहल

जल संरक्षण उपायों के उत्कृष्ट परिणाम खादी और ग्रामोद्योग आयोग के नासिक प्रशिक्षण केंद्र में देखे जा सकते हैं। 2 साल पहले बनाए गए चेक डैम ने केंद्र में सूखे नलकूपों को सम्पूर्ण रुप से भर दिया है। जल संसाधन में आत्मनिर्भरता, भारत के सतत विकास की कुंजी है।

केरल में नवीनीकृत खादी भवन का उद्घाटन

केरल के पयन्नूर खादी संस्था के नवीनीकृत खादी भवन का 25 अगस्त, 2020 को उद्घाटन किया गया । इस खादी भवन का नवीनीकरण खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विपणन अवसंरचना योजना के तहत प्रदान की गयी वित्तीय सहायता से किया गया है।

पयन्नूर फ़िरखा खादी ग्रामोद्योग संघ, केरल ने पारंपरिक परिधानों की श्रृंखला के तहत अपने एक नए उत्पाद “सेट मुंडू” को विक्रय हेतु बाजार में उतारा।

जगदलपुर में आयोग के कुम्हारों द्वारा एक छोटी लेकिन आदर्श पहल

खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हारों को सशक्त बनाकर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में हमारे शहरी स्थान से गौरया चिडियों की घटती आबादी के संरक्षण की एक छोटी लेकिन नेक पहल की है । फैलते कंक्रीट के जंगलों में गौरैयों के लिए ये मिट्टी के आश्रय एक अलग और नई पहल की शुरुआत कर सकते हैं।

(पृष्ठ 13 से आगे)

अरुणाचल प्रदेश में पहले सिल्क प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र के साथ खादी और पर्यटन को आयोग द्वारा प्रोत्साहन.....

वाले शहद के उत्पादन के लिए पर्याप्त वनस्पतियां हैं । सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल जीरो से महज 30 किमी पहले मुख्य राजमार्ग पर स्थित चुल्लियु एक सुंदर गांव है जो अपने पर्यावरण के अनुकूल रहने के तरीकों के लिए जाना जाता है। पर्यटक वहां तक आसानी से पहुंच सकते हैं जो स्थानीय कारीगरों के लिए फायदेमंद होगा।

श्री सक्सेना ने कहा, 'यह प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र अरुणाचल प्रदेश में अपने प्रकार का पहला केंद्र है और इससे पूरे क्षेत्र में बुनाई गतिविधियों को काफी बढ़ावा मिलेगा। कारीगरों को प्रशिक्षित करने और पूर्वोत्तर राज्यों के स्वदेशी एरी सिल्क के उत्पादन में मदद करने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन और इस क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा जो प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत संबंधी दृष्टिकोण के अनुरूप है।' उन्होंने कहा, 'उनके उत्पादों की मार्केटिंग के लिए केवीआईसी अपने ऑनलाइन पोर्टल पर एक विशेष पेज भी बनाएगा।'

इस पहल को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी लोगों- पुरुषों एवं महिलाओं के बीच पारंपरिक तौर पर एरी सिल्क और खादी सूती के कपड़े पहनने का रिवाज है जो उनके समतावादी आदिवासी समाज के लिए काफी महत्व रखता है। हालांकि इस राज्य के लोगों को असम सहित बाहरी बाजारों से भी सिल्क खरीदना पड़ता है।

केवीआईसी ने आदिवासी युवाओं की आधुनिक पसंद के अनुरूप नए डिजाइन तैयार करने के लिए एनआईएफटी, शिलॉन्ग और एनआईडी, जोरहाट जैसे पेशेवर डिजाइन संस्थानों के अलावा अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय डिजाइनरों की भी सेवाएं लेने की योजना बनाई है।

केवीआईसी पर्यटन स्थल जीरो पर आने वाले पर्यटकों को भी इस केंद्र पर आकर्षित करने की योजना बना रहा है। इससे स्थानीय कारीगरों को अपने उत्पादों के लिए एक बाजार सुनिश्चित होगा। बाजार की मांग को पूरा करने के लिए इस उत्पादन केंद्र को पर्याप्त उपकरणों से सुसज्जित किया जाएगा । केवीआईसी शुरुआती अवधि के लिए इस केंद्र को कच्चे माल के अलावा प्रशिक्षण एवं मजदूरी खर्च और नए डिजाइनों के प्रोटोटाइप विकसित करने की लागत भी प्रदान करेगा।

❑❑

(पृष्ठ 15 से आगे)

केवीआईसी द्वारा 'खादी एसेंशियल' और 'खादी ग्लोबल' को अवैधानिक रूप से खादी ब्रांड नाम के उपयोग के खिलाफ कानूनी नोटिस.....

को रोकना है।

केवीआईसी ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में उसने अपने ब्रांड नाम "खादी इंडिया" के किसी भी दुरुपयोग इसके ट्रेडमार्क के उल्लंघन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। केवीआईसी ने अब तक अपने ब्रांड के नाम का दुरुपयोग करने और खादी के नाम से उत्पादों को बेचने के लिए फैबइंडिया सहित 1000 से अधिक निजी फर्मों को कानूनी नोटिस जारी किए हैं। केवीआईसी ने फैबइंडिया से 500 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है जो मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

केवीआईसी ने खादी के नाम पर नकली वस्त्रों की बिक्री के कारण इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और खादी कारीगरों को मजदूरी के नुकसान के लिए इन फर्मों से हर्जाना भी मांगा है। हालांकि,कानूनी नोटिस दिए जाने के बाद अधिकांश कंपनियों ने केवीआईसी से माफी मांग ली और अपने उत्पादों तथा कपटपूर्वक खादी नाम के उपयोग वाले विज्ञापनों को वापस ले लिया है।

केवीआईसी ने 27 जुलाई, 2020 को चंडीगढ़ के एक व्यक्ति के खिलाफ अनधिकृत रूप से खादी फेस मास्क बताकर अपने फेस मास्क बेचने और इसके पैकेट पर प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज की। इससे पहले, केवीआईसी ने इस साल मई में दिल्ली की तीन कंपनियों को खादी के ब्रांड नाम के तहत नकली पीपीई किट बेचने के लिए कानूनी नोटिस जारी किए थे।

❖❖

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

अगरबत्ती के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनेगा भारत, गडकरी ने इससे जुड़ी स्कीम को दी मंजूरी

देश में दैनिक आधार पर अगरबत्ती की खपत करीब 1490 टन के आसपास है लेकिन स्थानीय स्तर पर 760 टन अगरबत्ती का ही उत्पादन होता है।

नई दिल्ली, पीटीआइ। MSME मंत्री नितिन गडकरी ने देश को अगरबत्ती के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ओर से प्रस्तावित रोजगार सृजन कार्यक्रम को अपनी मंजूरी दे दी है। एमएसएमई मंत्रालय ने कहा है कि 'खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन' का लक्ष्य देश में अगरबत्ती के उत्पादन में उल्लेखीय वृद्धि के साथ-साथ भारत के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराना है। मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रस्ताव को पिछले महीने MSME मंत्रालय के पास संस्तुति के लिए भेजा गया था। पायलट प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगी और जब इस कार्यक्रम पर पूरी तरह से अमल शुरू होगा तो अगरबत्ती उद्योग में हजारों रोजगार पैदा होंगे।

इस कार्यक्रम का लक्ष्य कारीगरों एवं स्थानीय अगरबत्ती उद्योग को सहायता उपलब्ध कराना है। देश में दैनिक आधार पर अगरबत्ती की खपत करीब 1,490 टन के आसपास है लेकिन स्थानीय स्तर पर 760 टन अगरबत्ती का ही उत्पादन होता है।

Big boost to local production; KVIC gets first order for 1200 quintal Mustard oil from ITBP

The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) has received the first order from Indo-Tibetan Border Police (ITBP) for supplying 1200 quintals of kacchi ghani mustard oil worth Rs 1.73 crore. The purchase order comes just weeks after the MoU signed between KVIC and ITBP on July 31, which is aligned with the Hon'ble Prime Minister's call for "Aatmanirbhar Bharat" and "Vocal for Local". The order will be supplied to ITBP within 30 days from the date of order.

Khadi India

Hon'ble Minister for MSME, Shri Nitin Gadkari lauded KVIC's efforts saying this would encourage local production and empower lakhs of people engaged with village industries.

This order will create additional jobs at the Khadi institutions manufacturing high quality kacchi ghani mustard oil. KVIC has instructed Khadi institutions to work in 3 shifts so as to complete the supply within the stipulated period of 30 days. This order will generate lakhs of additional man hours for Khadi artisans and thus encouraging local production. The development comes in wake of the instructions of Hon'ble Home Minister Shri Amit Shah to the paramilitary forces to encourage local products in a bid to support the "Aatmanirbhar Bharat Abhiyan". Shri Amit Shah has made it mandatory to sell only "Swadeshi" products through the CAPF canteens across India. The ITBP is the nodal agency appointed by MHA for the procurement of provisions on behalf of all paramilitary forces.

KVIC Chairman Shri Vinai Kumar Saxena welcomed the purchase order saying this was a major step towards strengthening our village industries and empowering the local artisans. "Only by encouraging local production and strengthening our village industries, we can overcome financial distress and create sustainable livelihood for our people. At the same time, our jawans at the border will get the best quality mustard oil. We will ensure the supplies are made before time," Saxena said. The KVIC and ITBP have signed the MoU for a period of one year which will be renewed further. The next products in the pipeline are cotton mats (dari), blankets, bed sheets, pillow covers, pickles, honey, papad and cosmetics, etc. The total value of oil and dari will be approximately Rs 18 crore.

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

COVID-19 impact: Soaring high! Khadi masks set to go global

By: Swapna Raghu Sanand | Updated: Aug 13, 2020 2:30 PM

Once known as the 'fabric of freedom', the Khadi, a part of India's freedom struggle legacy, has undergone remarkable transitions into mainstream society, becoming not only a sustainable fashion statement but also a conscious attempt to promote khadi artisans and local weaves.

The findings of the latest report published by Invest India on 'Khadi Masks: Protecting Lives and Livelihoods during COVID-19' is a fine reference on the future of Khadi masks in India.

COVID-19 impact: As face masks are becoming mandatory, Khadi masks are here to stay! Not just that, Khadi cotton and silk masks are set to be exported to other countries as well.

Once known as the 'fabric of freedom', the Khadi, a part of India's freedom struggle legacy,

Advertisement
WORD
Unlock your blog's true revenue potential
FINANCIAL EXPRESS
Biz News & Updates
Join Our Telegram Channel
You Design It. We Machine
OPEN

Stock Market
NSE BSE
NIFTY : 11386.05
COVID-19
Worldwide
Cases
Deaths

कोविड-19 के बीच नया स्टार्टअप: मंदिरों में चढ़ाए गए फूल व नारियल से 'हवन सामग्री'

मंदिरों की बढ़ेगी आय, मिलेगा रोजगार

शैलेंद्र शर्मा
patrika.com

जयपुर. मंदिरों में रोजाना चढ़ाए जाने वाले कई टन फूल तथा नारियल को उपयोग के बाद कचरे में फेंक दिया जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फूलों और नारियल के इस अपशिष्ट से 'हवन सामग्री' का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत यह कमाल किया है, राजधानी के कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान के दो वैज्ञानिकों ने। इन्होंने फूलों के प्राकृतिक रंग निकालकर पुष्प के अपशिष्ट से हवन सामग्री का निर्माण किया है। यह तकनीक एक स्टार्टअप है जो कोविड-19 के संकट के बीच युवाओं के रोजगार का बेहतर माध्यम बन सकती है।

बनाया जाता है पाउडर

आमतौर पर एक मंदिर में करीब 100 कि.ग्रा फूल और नारियल चढ़ाए जाते हैं। जिससे 10 से 15 कि.ग्रा पाउडर बनाया जाता है। हवन सामग्री में अन्य नैवेद्यम के साथ मिलाया जाता है। इसके सैंपल 250 ग्राम तथा 500 ग्राम के पैकिंग में तैयार किए हैं।

रोजाना 5 हजार की कमाई

हवन सामग्री को बाजार में करीब 150 रुपए प्रति किलोग्राम तक बेचा जा सकता है। अर्थात एक मंदिर से उतरने वाले फूल और नारियल से करीब 5000 रुपए प्रतिदिन की आय के साथ रोजगार मिल सकता है। इसके लिए फूल व नारियल का अलग से संग्रहण किया जाए।

संस्थान द्वारा वेस्ट प्रबंधन के अन्तर्गत मंदिरों में चढ़ाए गए फूल एवं नारियल के उपयोग से हवन सामग्री निर्माण की विकसित तकनीक सरल, सस्ती तथा पर्यावरण प्रिय है। -**बद्रीलाल मीणा,** राज्य निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

हर हाथ को काम देने को उठाया जा रहा कदम

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

कोरोना काल में हाथ कागज बनाने का सुअवसर-सक्सेना

जयपुर। कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान सांगानेर में प्रवासी श्रमिक, उद्यमी, नौकरी करने वाले, विद्यार्थियों को कोरोना काल में नया व्यवसाय करने के इच्छुक अभ्यर्थी जो ऐसे क्षेत्र में नवाचार कार्य करते हुए प्रकृति को संतुष्टि देते हुए ऐसे गैर सरकारी संस्थान के लोगों में हाथ कागज और उसके उत्पाद बनाने का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में समापन पर मुख्य अतिथि विनय कुमार सक्सेना अध्यक्ष खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बोधित करते हुए कहा कि कुमारप्पा राष्ट्रीय हाथ कागज संस्थान में जो भी अभ्यर्थी प्रशिक्षण कर रहे है या करेंगे उनको आयोग की हाथ कागज से सम्बंधित परियोजना से जोड़ा जायेगा एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के माध्यम से उनको

उद्योग स्थापित करने के हर संभव मदद किया जायेगा। उन्होंने संस्थान को इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन करने पर प्रशंसा की। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक बद्री लाल मीना ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए एवं उन्होंने भी सभी प्रशिक्षणार्थियों को हर संभव मदद खादी और ग्रामोद्योग की गतिविधियों के माध्यम से रोजगार से जोड़ने का आश्वासन दिया। मीना ने बताया कि राजस्थान से करीब 100 करोड़ मूल्य के हाथ कागज का निर्यात हो रहा है। नये प्रशिक्षणार्थी उद्यम स्थापित करेंगे और निर्यात करेंगे तो इससे राज्य में अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। इस अवसर पर संस्थान के वैज्ञानिक डॉ. अतुल कुमार, ईशा खान, डॉ. साक्षी एवं डॉ. सुनीता चौहान भी उपस्थित थे।

अनूठा प्रयोग: अपशिष्ट से बना रहे 'हवन सामग्री', जानें स्टार्टअप कैसे बन रहा रोज़गार और कमाई का माध्यम

मंदिरों में चढ़ाए गए फूल व नारियल से 'हवन सामग्री', स्वच्छ भारत अभियान का अनूठा प्रयोग, कोविड—19 के बीच नया स्टार्टअप, मंदिरों की बढ़ेगी आय, मिलेगा रोजगार

By: nakul
Updated: 22 Aug 2020, 06:52 PM IST
Jaipur, Jaipur, Rajasthan, India

'कंचन' का माध्याम बन रहा कचरा

जयपुर। यकीन नहीं होता लेकिन यह सच है, कचरे से जो कागज बन रहा है उसकी इतनी मांग है कि कोई आदमी मेहनत कर ले तो यह कागज कंचन प्राप्त करने का माध्यम बन सकता है। यह संभव कर दिखाया है जयपुर के सांगानेर स्थित कुमारप्पा हाथ कागज संस्थान ने, जिसके वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक ईजाद की है जिससे कई तरह के कचरे को प्रोसेस कर हाथ का कागज बनाया जा सकता है। विदेशों में इस तरह के कागज का जयपुर की एक फर्म करीब बीस करोड रूपए सालाना का निर्यात कर रही है। दावा किया जा रहा है कि पूरे देश ही नहीं, एशिया अथवा विश्व में इस तकनीक पर रिसर्च नहीं किया गया और इस पर जितने शोध किए गए हैं वे केवल यहीं पर हुए हैं और कहीं नहीं।

बद्री लाल मीणा

हाल ही में इसके निदेशक का पदभार संभालने वाले बद्रीलाल मीना ने इस तकनीक को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। वे कहते हैं कि 1994 में बने इस संस्थान में जितने भी शोध हुए हैं उनकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। हाथ से कागज बनाने की जो प्रकिया है वह बहुत ही सरल है और अगर कोई व्यक्ति मेहनत करे तो इससे लाखों-करोडों रूपए कमा सकता है। उनका कहना है कि संस्थान के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर इस तरह की तकनीक बनाई जिससे कचरा चाहे कैसा भी हो उसे प्रोसेस्ड कर हाथ का कागज बनाया जा सकता है।

मीना कहते हैं कि आकडे के पौधे, केले के पेड का ठूंठ, सरसों की तूडी, मंदिरों के बाहर पडे रहने वाले बेकार फूल, कपडों की सिलाई से बची कतरनें, रद्दी कागज, पुरानी चड्डी, बनियान, कहने का मतलब ज्यादातर बेकार चीजों से कागज बनाया जा सकता है। जयपुर में सांगानेर कस्बे के बीच से बहने वाले बम्बाला नाले में जो जलकुंभी पडी थी उससे भी संस्थान के वैज्ञानिकों ने हाथ का कागज तैयार कर दिया।

यह तय है कि कच्चे माल पर लागत बहुत कम आती है और तैयार माल महंगे दामों पर बिक रहा है। इस तरह से कचरे को कंचन (सोने) में तब्दिल किया जा सकता है। मीना दावा करते हैं कि युवा वर्ग इस तरह के काम से जुड जाएं तो बेरोजगारी की समस्या से निजात मिल सकती है।

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

Social Media Campaigns

• Posts Series •

सोशल मीडिया एवं ई-पेपर

Social Media Campaigns

• Instagram Grid •

• Special Day posts •

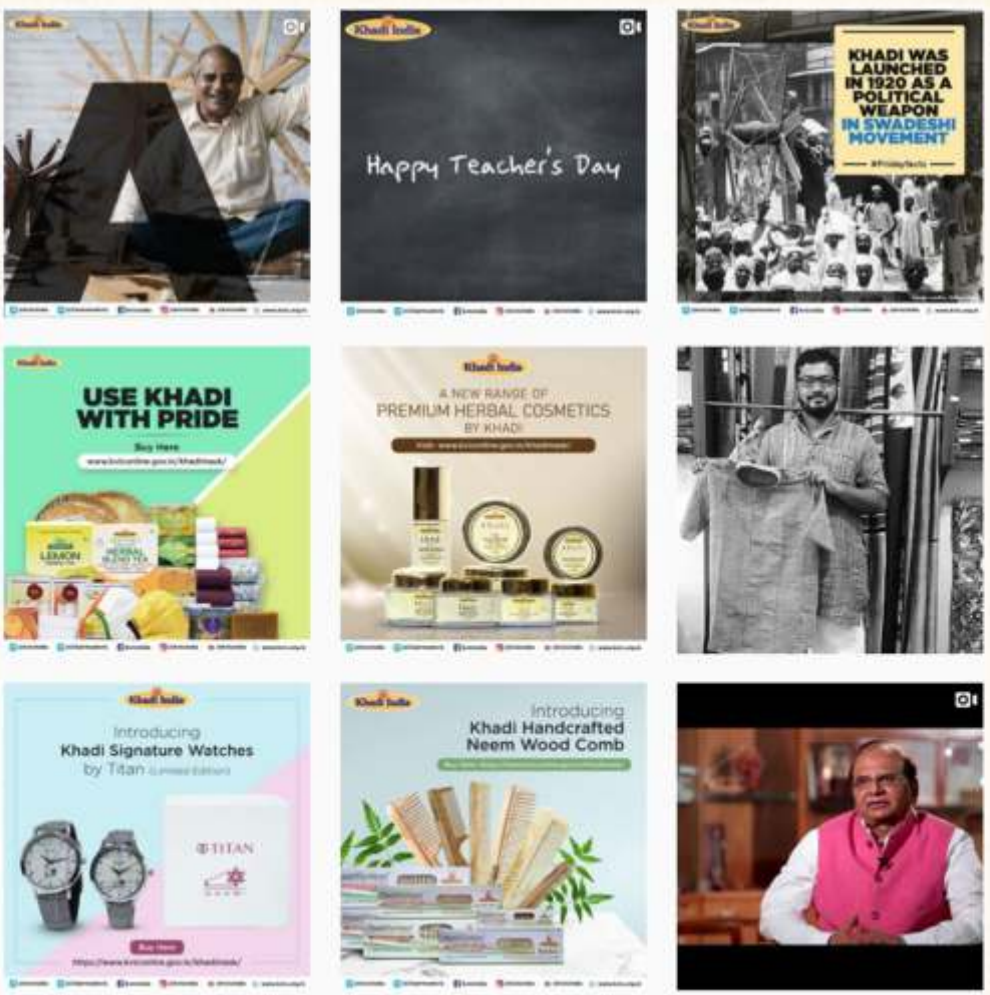

पर्यावरणानुकुल मनमोहक खादी डिजाइनर परिधान

बहुमुखी एवं मनमोहक
खादी डिजाइनर परिधानों
जैसे पर्यावरणानुकुल उत्पादों का एक स्थान
खादी वस्त्र, हर्बल उत्पाद,
रसायन रहित अगरबत्तियां,
विषाणु रहित एवं एन्टी फंगल शहद,
नैसर्गिक एवं आयुर्वेदिक सौन्दर्य उत्पाद
जैसे साबुन एवं शैम्पू,
हाथ कागज एवं पारंपरिक हस्तशिल्प
तथा अन्य उत्पादों की विशाल श्रृंखला

Khadi India

खादी और ग्रामोद्योग आयोग

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय,भारत सरकार
ग्रामोदय, 3, इर्ला रोड़, विले पार्ले (पश्चिम), मुम्बई-400 056.
वेबसाईट : www.kvic.org.in

"भारत में हम रोजगार सृजन करते है तथा समृध्दि बुनतें हैं"